



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3226]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 3226]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

का.आ. 4031(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् "मंत्रालय" कहा जाएगा), भारत सरकार, विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से "राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)" (जिसे इसके बाद योजना कहा जाएगा) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करता है, जो अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जनजातियों और भूमिहीन कृषि कामगारों एवं पारंपरिक दस्तकारों से संबंधित विद्यार्थी लाभार्थियों (जिसे इसके बाद लाभार्थी कहा जाएगा) को विदेश में उस देश के किसी प्राधिकृत निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तथा पीएच.डी. करने के लिए छात्रवृत्ति (जिसे इसके बाद लाभ कहा जाएगा) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3. तथा जबकि, उपर्युक्त योजना में किया गया व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

4. अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, नामतः:-

- (क) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।
- (ख) इस योजना के तहत हितलाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार नहीं है या उन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है, से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 31 मार्च, 2019 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, बशर्ते कि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईएडीआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।
- (ग) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस योजना का कार्यान्वयन करने का प्रभारी विभाग, जिससे एक व्यक्ति को आधार प्रदान करना अपेक्षित है, को लाभार्थियों, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा ऐसे मामलों में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में योजना का कार्यान्वयन करने के प्रभावी विभाग के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईएडीआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय में या स्वयं यूआईडीआई रजिस्टार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा प्रदान कराए।

बशर्ते कि उस समय तक जब व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन प्रदान किया जाएगा, नामतः:-

- (क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या
(ii) पैरा 4 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति।
- (ख) (i) फोटो सहित पासबुक, या
(ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; अथवा
(iii) राशन कार्ड, या
(iv) राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य फोटो पहचान का प्रमाण-पत्र; या
(v) पासपोर्ट; अथवा
(vi) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा
(vii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज,

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

5. उपर्युक्त योजना के तहत सुविधाजनक रूप से और बिना किसी कठिनाई के लाभार्थियों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेंगे:-

- क) योजनाओं के तहत आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मंत्रालय द्वारा मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो **31 मार्च, 2019** तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) सूची उपलब्ध करायी जाए।

ख) यदि योजना के लाभार्थी उनके निवास के समीप यथा प्रखंड अथवा तालुक अथवा तहसील के भीतर नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे इस योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध संबंधित वेबपोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को पैरा 4 के उप-पैरा (ग) में यथा विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना भारत के शासकीय राजपत्र में असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 14016/06/2017-डीबीटी]

कल्याणी चट्टा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2018

S.O. 4031(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly and in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

2. And whereas, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as Ministry), Government of India implements a Central Sector Scheme namely 'National Overseas Scholarship (NOS) (hereinafter referred to as Scheme) through Indian Missions abroad, which provides financial assistance in the form of Scholarship (hereinafter referred to as Benefit) to Student beneficiaries belonging to Scheduled Castes, Denotified, Nomadic and Semi- Nomadic Tribes and Landless Agricultural Labourers and Traditional Artisans (hereinafter referred to as Beneficiaries) for pursuing Master level courses and Ph.D abroad in accredited Institutions or Universities by an authorized body of that Country.

3. And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure to be incurred from the Consolidated Fund of India;

4. Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

- a) An eligible individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- b) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by **31st March, 2019**, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the

Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

- c) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through State Governments or UT Administrations is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if he/she has enrolled, his/her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of his/her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub- paragraph (b) of paragraph 4; and
(b) (i) Bank passbook with photograph; or
(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
(iii) Ration Card, or
(iv) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or
(v) Passport; or
(vi) Pan Card; or
(vii) any other documents specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

5. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries under the scheme, the Ministry through State Governments or UT Administrations shall make required arrangements including the following, namely:—

- a) Wide publicity through media and individual notices by Ministry, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by **31st March, 2019**, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.
- b) In case, the beneficiaries of the scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through State Governments or UT Administrations is required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number with other details as specified in the sub-

paragraph (c) of paragraph 4, with the concerned official or through a web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 14016/06/2017-DBT]
KALYANI CHADHA, Jt. Secy.